क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 335, शुक्रवार, 04 जनवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

रामम्ंदिर पर पासवान ने अध्यादेश का विरोध किया, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम

नई दिल्ली। भाजपा के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने वीरवार को राम मंदिर मुद्दे पर अध्यादेश का विरोध किया और कहा कि मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, 'राम मंदिर के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय दे वह सभी को स्वीकार्य होना चाहिए, चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों या अन्य समुदाय के लोग हों। हमारा रुख एक समान रहा है। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इंतजार करेंगे तो सभी अगर-मगर खत्म हो जाना चाहिए।' यह पूछने पर कि इस मुद्दे पर क्या वह अध्यादेश का समर्थन करेंगे तो पासवान ने कहा कि उनका रूख एकसमान रहा है और वह इसका समर्थन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि इस मुद्दे पर सरकार कोई निर्णय नहीं करेगी जब तक कि न्यायिक प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है। विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी समूह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने की मांग करते रहे हैं। लोजपा अध्यादेश का विरोध करने वाली भाजपा की दूसरी बड़ी सहयोगी है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथ यात्रा होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में भाजपा को रथयात्रा की अनुमति नहीं देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पार्टी की याचिका पर सात जनवरी को सुनवाई करने पर आज सहमत हो गया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस.के. कौल की पीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई का जिक्र किया गया था। पीठ ने सात जनवरी को इस पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। पार्टी की राज्य इकाई ने ''लोकतंत्र बचाओ रैली'' निकालने की अनुमति लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह रैली वर्ष 2019 आम चुनाव से पहले राज्य के 42 संसदीय क्षेत्रों से होकर निकाली जाएगी।

स्टार्टअप्स के लिए 2019 में भ्रष्टाचार, वित्तपोषण जुटाना प्रमुख चुनौती: रिपोर्ट

नई दिल्ली। देश में बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स, लघु एवं मझोले उपक्रमों का मानना है कि वर्ष 2019 में भ्रष्टाचार, अफसरशाही की अक्षमता, कर्ज और कोष जुटाना उनके लिए प्रमुख चुनौती होगी। नागरिक कार्य मंच लोकलसर्किल्स की एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है। यह रिपोर्ट 15,000 से अधिक स्टार्टअप्स, एसएमई तथा उद्यमियों की राय पर आधारित है। 45 प्रतिशत लोगों का कहना है कि नए साल में उनके समक्ष प्रमुख चुनौती भ्रष्टाचार और अफसरशाही की अक्षमता है। इसके बाद 37 प्रतिशत का कहना है कि कर्ज जुटाना प्रमुख चुनौती है जबकि 18 प्रतिशत ने कारोबार वृद्धि को प्रमुख चुनौती बताया। हाल के समय में कई स्टार्टअप्स और एंजल निवेशकों ने एंजल कोषों पर कराधान को लेकर आयकर विभाग ने उन्हें मिले नोटिस पर चिंता जताई है। इस अध्ययन में शामिल 38 प्रतिशत लोगों का कहना था कि उन्हें कम से कम एक नोटिस मिल चुका है।

भाजपा सरकार

मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में 'जय अनुसंधान' जोड़ा

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत लाल बहादुर शास्त्री के प्रसिद्ध नारे 'जय जवान जय किसान' और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नारे 'जय विज्ञान' में बृहस्पतिवार को 'जय अनुसंधान' जोड़ दिया। वह जालंधर में आयोजित 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में 'भविष्य का भारत : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' विषय पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन और कार्य प्रौद्योगिकी विकास तथा राष्ट्र निर्माण के साथ गहरी मौलिक अंतर्दृष्टि के एकीकरण का शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा, ''आज का नया नारा है- जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। मैं इसमें जय अनुसंधान जोड़ना चाहूंगा।'' मोदी ने कहा कि यह विज्ञान ही है जिसके माध्यम से भारत अपने वर्तमान को बदल रहा है और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, ''भारतीय विज्ञान के लिए 2018 एक अच्छा वर्ष रहा। इस साल हमारी उपलब्धियों में उड़ुयन श्रेणी के जैव ईंधन का उत्पादन, दृष्टिबाधितों के पढ़ने में मदद करने वाली मशीन -दिव्य नयन, सर्वाइकल कैंसर, टी बी, डेंगू के निदान के लिए किफायती उपकरणों का निर्माण और भूस्खलन के संबंध में सही समय पर चेतावनी प्रणाली जैसी चीजें शामिल हैं।'' इस दौरान मोदी ने 'इज ऑफ लिविंग' पर तेजी सो काम करने को कहा ताकि भारत दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व कर सके। उन्होंने कहा कि 'इज ऑफ डूईंग बिजनेस' की तरह ही 'इज ऑफ लिविंग' पर भी तेजी से काम करना होगा। उन्होंने कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर टेक्नॉलॉजी, ड्रोन और विग डाटा का पैकेज तैयार करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने, संवेदनशील संस्थानों की साइबर सुरक्षा अभेद्य बनाने तथा कम बारिश वाले इलाकों में सूखा प्रबंधन की नयी तकनीक पर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन सवालों के जवाब खोजने होंगे। विज्ञान को आम लोगों के जीवन से जोड़ना होगा। श्री मोदी ने कहा,''अब रूकने, किसी के लिए इंतजार करने का वक्त नहीं है। अब हमें दुनिया में नेतृत्व लेना होगा। सरकार हर तरह की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। हमें विज्ञान की मदद से नया भारत बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।''

कश्मीर में आम चुनावों के साथ चुनाव कराने में नहीं कोई आपत्तिः राजनाथ

नेशनल डेस्क।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरवार को जम्मू कश्मीर में पिछले साढ़े चार साल में स्थिति बहुत बिगड़ जाने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने को लेकर प्रतिबद्ध है तथा उसे राज्य में आम चुनावों के साथ चुनाव करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा बल मांगे जाने पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी मुहैया कराये जाएंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के सांविधिक संकल्प पर राज्यसभा में हुई चर्चा के जवाब में यह बात कही। उनके जवाब के बाद उच्च सदन ने इस संकल्प को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। गृहमंत्री ने बुधवार को कहा था कि जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होगा, इसका निर्णय भारत निर्वाचन आयोग को लेना है। राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है। उन्होंने कहा था कि चूंकि पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं, लिहाजा राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए भी अनुकूल वातावरण है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से अपना गठबंधन समाप्त कर उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद विधानसभा राज्यपाल शासन के अधीन निलंबित अवस्था में थी। आजादी के बाद यह तीसरा मौका है, जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है। राज्य की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ही कांग्रेस भी जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रही है।

राजीव गांधी प्रस्ताव पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा, सिरसा का आरोप- मेरी पगड़ी उतारी गई

नई दिल्ली।

दिल्ली विधानसभा में भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी संबंधी एक हालिया विवादास्पद प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ जिसके बाद विपक्ष के तीन विधायकों को दिनभर के लिए निलंबित कर दिया गया। भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा को सदन के बीचों बीच आने पर मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ हाथापाई की गई और सदन के स्थगन के दौरान उनकी पगड़ी को कथित रूप से बलपूर्वक हटाया गया। उन्होंने कहा कि क्या सिख दंगा पीड़ितों के लिए विधानसभा में आवाज उठाए ये गुनाह है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा में दंगा पीड़ितों के लिए आवाज उठाने पर एक सिख विधायक की पगड़ी तक उतार दी गई और उन्होंने इसके लिए सीधा-सीधा विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को जिम्मेदार ठहराया। सिरसा ने कहा कि अलका लांबा को भी विधानसभा से बाहर जाने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट भी की गई और इस दौरान दिल्ली विधानसभा के कैमरे भी बंद कर दिए गए। उल्लेखनीय है कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक ने राजीव गांधी को प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान ''भारत रत्न'' वापस लेने की मांग वाला एक प्रस्ताव पेश किया था। सिरसा ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस ''हालिया प्रस्ताव में'' कथित ''बदलाव'' को लेकर ''अध्यक्ष राम निवास गोयल को हटाने'' के लिए नोटिस पेश किया था। गोयल ने कहा कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रकार का नोटिस 14 दिन पहले दिया जाना चाहिए। जब अध्यक्ष ने विपक्ष का अनुरोध ठुकरा दिया तो सिरसा सदन के बीचों बीच आ गए।

पत्रकार पर निशाना साधकर राहुल गांधी ने दिखा दिया अपना असली डीएनए : जेटली

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुबह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सिलसिलेवार कई ट्वीटस किए। जेटली ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि पत्रकार पर हमला बोलकर कांग्रेस अध्यक्ष ने आपातकाल की तानाशाह के पोते ने आखिर अपना असली डीएनए दिखा दिया। राहुल ने बुधवार को लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि मोदी ने ''पूर्वनियोजित साक्षात्कार'' दिया। राहुल ने कहा कि मोदी का इंटरव्यू लेने वाली पत्रकार सवाल भी पूछ रही थी और खुद ही जवाब भी दे रही थी। जेटली ने ट्वीट किया कि राहुल ने एक स्वतंत्र संपादक को डराया और धमकी दी है। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, छद्म उदारवादी चुप क्यों हैं? एडिटर्स गिल्ड की प्रतिक्रिया का इंतजार है। वहीं भाजपा मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने देर रात दिए बयान में मोदी का साक्षात्कार लेने वाली पत्रकार का बचाव किया और कहा कि गांधी द्वारा मीडियाकर्मी पर निशाना साधना पत्रकारों के बारे में कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि राहुल ने लोकसभा में बोलते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने इंटरव्यू में राफेल पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया जबकि पूरा देश उनसे सवाल पूछ रहा है। राहुल ने कहा कि मोदी में हिम्मत नहीं है ।

शिवसेना का तीखा हमला, पूछा- भाजपा सरकार के शासन में नहीं तो कब बनेगा राम मंदिर

मुंबई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए शिवसेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे इस बात पर ताज्जुब है कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो कब होगा। पार्टी ने कहा कि अगर राम मंदिर का निर्माण 2019 चुनावों से पहले नहीं हुआ तो यह देश के लोगों को धोखा देने जैसा होगा जिसके लिए भाजपा एवं आरएसएस को उनसे माफी मांगनी होगी। केंद्र एवं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी शिवसेना ने हालिया साक्षात्कार में मोदी की टिप्पणी के लिए उनपर हमला बोला है। मोदी ने कहा था कि मंदिर निर्माण पर सरकार कोई भी कदम न्यायिक प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही उठाएगी। इस साक्षात्कार को कई टीवी चैनलों ने प्रसारित किया था। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में कहा, वह (मोदी) राम के नाम पर सत्ता में आए थे हालांकि उनके मुताबिक भगवान राम कानून से बड़े नहीं हैं। अब सवाल यह है कि अगर बहुमत वाली सरकार में मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो कब बनेगा।'' संपादकीय में कहा गया कि मोदी सरकार ने गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल की भव्य प्रतिमा बनाई है लेकिन राम मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सरदार' वाला साहस नहीं दिखाया। साथ ही कहा कि यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इसमें बताया गया कि राम मंदिर के लिए आंदोलन 1991-92 में शुरू हुआ था और सैकड़ों 'कारसेवकों' ने अपनी जान गंवाई थी। इसमें पूछा गया, किसने यह नरसंहार किया और क्यों? एक ओर सैकड़ो हिंदू कारसेवक मारे गए साथ ही मुंबई बम धमाकों में दोनों पक्ष (हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय) के सैकड़ों लोग मारे गए। अगर फैसला उच्चतम न्यायालय को ही करना था तो यह नरसंहार एवं खूनखराबा क्यों?'' ।

प्रधानमंत्री राफेल की हर परीक्षा में फेल हुएः कांग्रेस

नई दिल्ली।

राफेल मामले में राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी बहस और 'ओपन बुक परीक्षा' की चुनौती दिए जाने के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री राफेल से जुड़ी हर परीक्षा में फेल हो चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,'इसमें कोई संदेह नहीं है कि वित्त मंत्री अरुण जेतली अब इस सरकार के 'डिफेंसिव मिनिस्टर' बन गए हैं। प्रधानमंत्री जी राफेल की हर परीक्षा में फेल हो गए हैं। वह लोगों को 'एक्जाम वॉरियर' के बारे में किताब लिखकर सिखाते हैं। आज एक्जाम वॉरियर एक्जाम छोड़कर खुद भाग रहे हैं।' कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को राफेल मामले में सीधी बहस की चुनौती दी थी। वित्त मंत्री अरुण जेतली के राफेल मामले पर लोकसभा में दिए भाषण का उल्लेख करते हुए सिंघवी ने कहा,'जेतली ने खुद माना 36 राफेल विमानों की खरीद का सौदा 36 हजार करोड़ रुपए का है। इस हिसाब से एक विमान की कीमत 1600 करोड़ रुपए हुई। इसका मतलब यह है कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो विमान 1600 करोड़ रुपए की कीमत में खरीदे जा रहे हैं।' उन्होंने कहा,'अगर हमें विमानों की तत्काल जरूरत थी और विमान संप्रग सरकार के समय की तुलना में सस्ते मिल रहे थे तो फिर विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 क्यों की गई? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रावधान क्यों बदला गया?' सिंघवी ने पूछा,'ऑफसेट अनुबंध उसे क्यों दिया गया जिसने कभी कागज वाला जहाज भी नहीं बनाया?' एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'राफेल मुद्दा आज हर आदमी के जेहन में है।

जब 30 हजार करोड़ रुपए एक निजी कारपोरेट को दे दिए जाएंगे तो हमें और आप को फर्क क्यों नहीं पड़ेगा?' अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए सिंघवी ने कहा, 'हाल के समय में तीन रिपोर्ट सामने आई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल में बैंक जालसाजी के मामलों में 72 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

अध्यादेश न लाने के प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद गर्माई सियासत

जालंधर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समाचार एजैंसी ए.एन.आई के इंटरव्यू में राम मंदिर पर दिए वक्तव्य पर विश्व ड्क्षहदू परिषद ने असहमति जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में साफ-साफ बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही उनकी सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री के इस बयान का जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए समर्थन किया है वहीं विश्व हिन्दू परिषद ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि वी.एच.पी. राम मंदिर के निर्माण पर लंबा इंतजार नहीं कर सकती है। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मोदी राम मंदिर पर कानून बनाकर इसके निर्माण का रास्ता साफ करें। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर पर हमारा अगला कदम क्या होगा इसका निर्णय प्रयागराज में कुंभ के मौके पर 31 जनवरी को धर्मसभा में लिया जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट अब 4 जनवरी को सुनवाई करेगा हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राम मंदिर उनके लिए प्राथमिकता का विषय नहीं है। 1528 में मुगल हमलावर बाबर के जनरल मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबर की शान में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तब से अब तक तकरीबन 500 साल होने को आए हैं। साल 1885 से राम वादी के रूप में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। 30 सितम्बर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। हाइकोर्ट ने तीनों पक्षों रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में 2.77 एकड़ जमीन को बराबर बांटने का आदेश दिया। फैसले के खिलाफ ड्क्षहदू महासभा तथा सुन्नी सैंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आए फैसले को 9 साल होने वाले हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्राथमिकता का मुद्दा नहीं माना है। अगर कुछ वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ भी जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि फैसला सभी पक्षों के हित में होगा। कानूनी प्रक्रिया लम्बी भी खिंच सकती है। राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के लिए चारों तरफ से मोदी सरकार पर दबाव बन रहा है लेकिन ऐसी क्या बात है जो लोकसभा में बहुमत होने और राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा सरकार अध्यादेश नहीं ला रही है या यूं कहें लाना नहीं चाहती है। लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों से 282 सीटों तक का सफर तय करने वाली भाजपा ने जब चाहा राम मंदिर मुद्दे का इस्तेमाल किया और जब चाहा धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए उसे त्याग दिया। कहते हैं कि घोषणापत्र राजनीतिक दल की आत्मा होती है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर भाजपा की नीयत क्या है वह उसके घोषणापत्रों से पता चलती है। भाजपा की वैबसाइट में 1998 से पहले के घोषणापत्र नहीं हैं। 1998 से 2014 तक के घोषणापत्रों में राम मंदिर को लेकर भाजपा की भाषा किस तरह

जरूरत के हिसाब से बदलती रही है वह आगे आप स्वत जान जाएंगे।

संपादकीय

वर्तमान 16वीं लोकसभा के 543 में से केवल 35 सांसद पांच वर्षों में मिली आवंटित राशि 25 करोड़ रुपए का शत-प्रतिशत खर्च कर पाए हैं। पता चलता है कि प्रतिनिधि विकास कार्यों के प्रति किस कदर उदासीन हैं। इतना ही नहीं दक्षिणी भारत के किसी भी राज्य में राशि का समूचा उपयोग नहीं हुआ है। सांसदों का यह रवैया विकास की कमजोर अवधारणा को प्रदर्शित करता है।

सांसद निधि के खर्च पर उठे सवाल

यह चिंता का विषय है कि सांसद-विधायकों को अपनी इच्छानुसार क्षेत्रों के विकास के लिए जो धनराशि आवंटित की जा रही है, वह पूरी खर्च नहीं हो रही है, जबकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस राशि को विवेकानुसार खर्च करने का पूरा अधिकार है। कई जगह से इसे नौकरशाह एवं ठेकेदारों के साथ बंदरबांट करने की शिकायत भी आई हैं। तो कहीं अधिकारियों द्वारा अड़ंगा लगाने और सिफारिश के बावजूद समय पर राशि आवंटित नहीं करने की शिकायतें भी जनप्रतिनिधियों ने की हैं। इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे प्रतिनिधियों का नैतिक बल कमजोर करने का कारण मानते हुए बंद भी कर दिया है। इसके उलट दिल्ली की आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राशि और उससे किए जाने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से ऑनलाइन कर दिया है। गोया अब कोई भी नागरिक वेबसाइट खोलकर कार्य की जानकारी ले सकता है। यह राशि अब तक दो किश्तों में दी जाती है, जिसे एकमुश्त देने का प्रावधान किया जा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2014 से अब तक 543 में से केवल 35 लोकसभा क्षेत्रों में ही सांसद निधि का इस्तेमाल स्वीकृत परियोजनाओं के मुताबिक हुआ है।

वर्तमान 16वीं लोकसभा के 543 में से केवल 35 सांसद ही पांच वर्षों में मिली आवंटित राशि 25 करोड़ रुपए का शत-प्रतिशत खर्च कर पाए हैं। इससे पता चलता है कि प्रतिनिधि विकास कार्यों के प्रति उदासीन हैं। दक्षिणी भारत के किसी भी राज्य में राशि का समूचा उपयोग नहीं हुआ है। जबकि शिक्षा व राजनीतिक जागरूकता की दृष्टि से इन्हें अन्य राज्यों के सांसदों के मुकाबले श्रेष्ठ माना जाता है। आदर्श ग्राम योजना के तहत जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे, उन्हें इस राशि से ठीक से विकसित कर सकते थे, लेकिन एक भी सांसद ने आदर्श ग्राम योजना की अवधारणा को जमीन पर नहीं उतारा। दरअसल प्रतिनिधि योजना के अमल में आने वाले व्यवधानों के लिए अधिकारियों पर दोषारोपण करते रहे हैं क्योंकि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहती है। योजना की राशि भी सांसद या विधायक के खाते की बजाय जिला योजना मंडल के खाते में आती है, जिसके प्रमुख जिलाधीश होते हैं। इस बिंदु को भी प्रतिनिधि योजना के नाकाम होने का कारण मानते हैं, जबकि यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई, जिससे प्रतिनिधि मनमाने ढंग से राशि खर्च नहीं करने पाएं।

साफ है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही राशि के व्यय के प्रति लापरवाह हैं। इसीलिए केंद्रीय सूचना आयोग ने इस योजना पर अमल के लिए नई सरंचनागत संस्था की जरूरत जताई है। इसे पारदर्शी बनाने के साथ निर्वाचित प्रतिनिधि को उत्तरदायी भी बनाया जाएगा। इस योजना को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने का भी प्रावधान हैं। ऐसा इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कई प्रतिनिधि इस राशि से चौराहों पर अपने पूर्वजों की मूर्तियां लगाने और अपने अनुयायियों के परिजनों की बीमारी के लिए इस मद से धन का आवंटन कर रहे हैं। कई प्रतिनिधि राजनीतिक लाभ की दृष्टि से राशि को ठीक चुनाव के पहले सरपंचों की मांग के अनुसार खर्च करते हैं। यह प्रलोभन एक तरह से मतदाताओं को वोट के लिए दी जाने वाली घूस की तरह है। सांसद निधि योजना की शुरुआत 1993 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने की थी। इसके तहत लोकसभा व राज्यसभा के सभी सांसदों को पांच करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इसी विधान के अनुसार राज्यों ने इसे अपनाया व विधायकों को विकास निधि देने लग गए। इसका उद्देश्य विकास कार्यों का विकेंद्रीकरण करना था। नरसिंह राव की मंशा थी कि जनहित के ऐसे छोटे-छोटे कार्य, जो बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, वे इस राशि से प्रतिनिधि की सिफारिश पर कर लिए जाएं। किंतु योजना उद्देश्य पर खरी नहीं उतरी।

दरअसल, जिस निधि को विकास का पर्याय माना गया था, वह जनप्रतिनिधियों का नैतिक बल कमजोर करने वाली साबित हुई। निधि के वितरण में सांसद और विधायकों द्वारा कमीशनखोरी की जानकारियां तो आमफहम हुईं। इस कारण इसे अनैतिकता का पर्याय माना गया। यह स्थिति सांसद और विधायकों की राजनीतिक जमीन तो पुख्ता कर रही है, लेकिन नीति निर्माण और निगरानी जैसे जो उनके मूल काम हैं, उनसे ध्यान हटा रही है। बावजूद मनमोहन सिंह सरकार ने आनन-फानन में निधि को दोगुना कर दिया था। जबकि इसी समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक निधि खत्म करने की पहल की थी। योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष मोटेंकसिंह अहलूवालिया भी राशि बढ़ाए जाने के खिलाफ थे। चूंकि सांसद हो या विधायक सबकी प्रतिबद्धता अपने दल से जुड़ी होती है। ज्यादातर विकास निधि वितरण में पक्षपात बरतते हैं। उन पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से राशि का वितरण किया जाता है, जो सांसदों के नुमाइंदे होने के साथ क्षेत्र में उनके राजनीतिक हित साधने में लगे रहते हैं। मसलन इस राशि से समर्थकों को उपकृत किया जाता है। लिहाजा सार्वजनिक धन अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के काम आ रहा है। इस कारण न तो समावेशी विकास का आदर्श सामने आया है और न ही उन दूरांचलों में बुनियादी विकास की जरूरतें पूरी हुई हैं, जो आदिवासी ग्राम हैं। आज भी हम यदाकदा देखते हैं कि ग्रामीण बच्चे पेड़ों से रस्सी बांधकर और ट्यूबों की नावें बनाकर नदी नाले पार कर रहे हैं। इस कारण इस विकास निधि के औचित्य पर सवाल उठते हैं।

वहीं, सांसद निधि को अंसवैधानिक भी माना जाता रहा है। दरअसल संवैधानिक ढांचागत व्यवस्था के अनुसार जब जिस काम के लिए प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायतें हैं तो विकास निधि के वितरण की जवाबदारी विधायिका पर क्यों? संविधान के अनुसार तो सांसद-विधायकों का मुख्य काम जनहितैषी नीतियों का निर्माण कर उनका क्षेत्र में ईमानदारी से अमल कराना है, जिससे राशि का दुरुपयोग न हो और विकास कार्यों की गुणवत्ता भी बनी रहे। इसके संवैधानिक औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए योजना आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग और नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक के अलावा कई संविधानविदों तथा गैर सरकारी संगठनों ने भी इस व्यवस्था को संविधान विरोधी माना है। यही नहीं इस निधि को राज्यों के स्थानीय और स्वायत्तशासी निकायों के कार्यों में हस्तक्षेप भी माना गया है। योजना के साथ यह दलील भी जुड़ी है कि यह सांसद और विधायकों को कर्तव्यों से विमुख करती है क्योंकि वे अब नीति निर्माण और निगरानी जैसे दायित्वों का निर्वाह करने की बजाय खुद विकास कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ गए हैं। नतीजतन विधायिका, नौकरशाह और ठेकेदारों का एक ऐसा गठजोड़ भी वजूद में आ गया है, जो इस अरबों रुपए की निधि को कैसे निजी संपति का हिस्सा बनाया जाए, इस विधान में लगा रहता है। इसी सोच का परिणाम था कि कुछ साल पहले एक समाचार चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में कुछ सांसदों को विकास निधि वितरण के लिए कथित ठेकेदारों से रिश्वत लेते हुए दिखाए गए थे। ऑपरेशन की सत्यता प्रमाणित होने के बाद तत्काल इन 11 सांसदों की लोकसभा से सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। इस निधि के प्रावधान के बाद ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की निजी संपत्ति आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ी है। इसका खुलासा स्वयं प्रतिनिधि चुनाव के समय प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्रों में देने की मजबूरी झेलते हैं।

बहरहाल ढाई दशक से चली आ रही इस योजना के कोई विशेष बुनियादी लाभ तो हुए नहीं, अलबत्ता योजना सांसद और विधायकों का चारित्रिक पतन का पर्याय जरूर बन गई हैं। लिहाजा इस योजना को खत्म करना बेहतर होगा। वरना सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता रहेगा।

प्रमोद भार्गव
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

महंगा चुनाव देश के लिए घातक

ऐसी संभावना है कि इसी साल होने वाले लोकसभा के चुनाव में डेढ़ लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकता है। यह आंकड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि चुनाव में खर्च की जाने वाली यह रकम बेनामी होती है। चुनाव को महंगा करने से बचाने की तरकीब अब हमें ढूंढनी ही होगी।

नए साल के साथ ही लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। चार माह बाद चुनाव में होने वाले खर्च को लेकर जो आंकड़ा सामने आया है, वह चौंकाने वाला है। खर्च का आकलन करने वाली संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार चुनाव में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकता है। लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम चुनाव के छह से आठ महीने बाद महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, बिहार और दिल्ली में चुनाव हुए थे। दिल्ली को छोड़ चारों राज्यों की सरकारें समय से पहले विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ चुनाव करा सकती हैं। पिछले साल के शुरू में हुए कर्नाटक विधानसभा के चुनाव अब तक के सबसे महंगे चुनाव थे। इससे पहले गुजरात का नंबर था, जिसने चुनाव में बेतहाशा खर्च किया था। चुनाव में बढ़ता खर्च इसलिए भी चिंता का कारण है कि इस दौरान बड़ी मात्रा में कालाधन बाहर आता है।

अभी पांच राज्यों के चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत ने कहा भी था कि तमाम सख्ती के बाद भी कालेधन पर रोक नहीं लग पाई। इसे आंकड़ों से समझें, तो पता चलेगा कि 1951 में जहां प्रति वोटर 60 पैसे खर्च आया था। 2009 में यह 12 रुपए प्रति मतदाता था, जो वर्ष 2014 में बढ़कर 17 रुपए हो गया, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में 5.06 करोड़ वोट पड़े और खर्च 10 हजार 500 करोड़ रुपए था। यानी प्रति मतदाता 2100 रुपए खर्च करना पड़ा। जाहिर है कि यह रकम 'इधर-उधर' से ही जुटाई गई होगी। हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए है, लेकिन पार्टियों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। केंद्रीय नेताओं की हवाई यात्राओं का खर्च व विज्ञापनों का खर्च पार्टी उठाती है। प्रत्याशी इसी खर्च का फायदा उठाते हैं और पार्टियां भी कभी-कभी उनके ज्यादा खर्च को अपने खाते में जोड़कर दिखा देती हैं। इसका नुकसान यह होता है कि चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी तो कमाई में जुट जाता है, पार्टी को उपकृत करने के लिए भी धन बटोरने लगता है। इन परिस्थितियों में चुनाव जनता की भलाई या मजबूत लोकतंत्र का आधार न होकर कमाई का जरिया बन जाता है।

सो, यहीं से उन बड़े-बड़े घपलों-घोटालों की शुरुआत होती है, जो हमारे लोकतंत्र को लगातार खोखला करते जा रहे हैं और आम जनता में राजनीति को लेकर नफरत का भाव विकसित कर रहे हैं। सवाल है कि अगर यह समस्या इतनी गंभीर है, तो इसका समाधान ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब यह है कि सरकारें और राजनीतिक पार्टियां चाहती ही नहीं कि इस बीमारी का इलाज हो, क्योंकि वे जानती हैं कि इसके इलाज की बात करना खुद पर ही नकेल कसने जैसा है। यही वजह है कि चुनाव सुधार कोई भी बात किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडा में आज तक जगह नहीं बना पाई है। लेकिन अब इस दिशा में सोचना ही होगा।

नायडू की दलील में दम नहीं

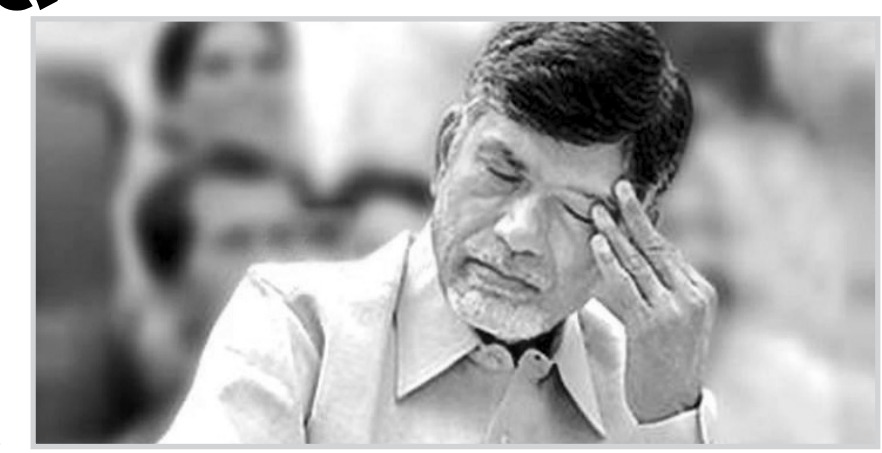

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के उस नियम को खत्म कर दिया है, जिसमें दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले आदमी को स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी। यह सही कदम नहीं है। आज जब देश बढ़ती जनसंख्या की वजह से तमाम समस्याएं भोग रहा है, ऐसे में किसी भी राज्य के सीएम को यह हक नहीं कि वह ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत करने लगे।

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे दो से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ऐसा करने वाले कपल को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। नायडू ने अपने राज्य के उस नियम को खत्म कर दिया है, जिसमें दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले आदमी को स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस नियम के पीछे नायडू का तर्क है कि आंध्र प्रदेश में 10 साल की जनसंख्या वृद्धि में 1.6 प्रतिशत की कमी आई है, जिससे राज्य की डेमोग्राफी पर असर पड़ा है। नायडू ने जनसंख्या वृद्धि की यह बात पहली बार नहीं की है। मार्च 2016 में भी नायडू ने कहा था कि राज्य की जनसंख्या में भारी कमी आई है, ऐसी ही दिक्कत का सामना चीन और जापान कर रहे हैं, जहां पहले जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से परिवार नियोजन लाना पड़ा फिर वहां युवाओं की जनसंख्या कम हो गई। नायडू की बात में गंभीरता का भाव नहीं है। वे कह रहे हैं कि उनके राज्य की जनसंख्या कम हो गई है। यह तो देश के किसी भी राज्य के लिए बेहतर उदाहरण है।

नायडू की पहचान विकास की बेहतर सोच रखने वाले नेता के रूप में होती है। आंध्रप्रदेश में उनके द्वारा किए गए विकास को कई राज्यों में अपनाया गया है। ऐसे में नायडू को ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करने से पहले देश की स्थिति पर नजर जरूर डालनी चाहिए थी। देश में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय, निर्धनता में वृद्धि, मकानों की समस्याएं, कीमतों में वृद्धि और कृषि विकास में बाधा, बचत व पूंजी निर्माण में कमी, जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक व्यय, अपराधों में वृद्धि तथा शहरी समस्याओं में वृद्धि जैसी ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की ही है। पूंजीगत साधनों की कमी के कारण रोजगार मिलने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। फिर भी नायडू का मानना है कि जापान और चीन जैसे देशों ने जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ सख्त कानून बनाए थे लेकिन अब वहां ज्यादातर जनसंख्या बूढ़े लोगों की हो गई है और ये दोनों देश काफी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। किसी भी प्रोग्रेसिव देश के लिए यह जरूरी है कि उनकी जनसंख्या में ज्यादा से ज्यादा युवा हों।

2011 में हुई जनगणना के मुताबिक, जनसंख्या के आधार पर आंध्र प्रदेश का देश में 10वां नंबर था। तेलंगाना राज्य अलग होने से पहले आंध्र की कुल आबादी 8.46 करोड़ थी। इसके बाद जून 2014 में तेलंगाना अलग हुआ। आंध्र सरकार का कहना है कि राज्य में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। सरकार के मुताबिक, राज्य में बर्थरेट 2014 में 1000 पर 37 प्रतिशत था, जो गिरकर अब 2018 में 10.51 प्रतिशत पर आ गया है। ऐसे में देखा जाए तो यह स्थिति तब आई है, जब जनसंख्या विभक्त होकर दो राज्यों में चली गई। अगर दोनों राज्यों की जनसंख्या को मिलाकर देखें तो यह कहीं से कम नहीं होगी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश की हालत किसी से छिपी नहीं है। यूपी में जनसंख्या करीब 20 करोड़ 40 लाख के आसपास है। वहां के संसाधन और बेरोजगारी किसी से छिपी नहीं है। यूपी के भी तीन टुकड़े करने की बात की जा रही है, अगर ऐसा हुआ, तो निश्चित रूप से जनसंख्या भी विभक्त हो जाएगी। ऐसे में क्या तब सारे राज्य जनसंख्या बढ़ाने की वकालत करने लग जाएंगे? यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी शहर या राज्य में बढ़ने वाली जनसंख्या का भार अंततः देश पर ही पड़ता है और दंश सभी भुगतते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की शोध शाखा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत के पास अपनी स्थिति को बदलकर विकसित देशों की कतार में शामिल होने के लिए सिर्फ एक दशक का वक्त है। इसके लिए भारत को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। अगर वह इस मोर्चे पर विफल हुआ तो देश की युवा आबादी का लाभ नुकसान में बदल जाएगा। जनसंख्या तथा आर्थिक विकास में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या के आकार, बनावट तथा कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। 30 अप्रैल 2013 को जारी हुए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या बढ़कर 121.07 करोड़ हो गई है। यानी देश की जनसंख्या में 17.7 फीसद की वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में जनाधिक्य की समस्या बनी हुई है और विगत पांच दशकों में जनसंख्या में निरंतर तीव्र वृद्धि के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या की यह तीव्र वृद्धि आर्थिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर रही है।

दुनिया में कई देशों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है भारत उनमें सबसे आगे है। अगर इसी रफ्तार से भारत की जनसंख्या बढ़ती रही तो कुछ ही सालों में भारत चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या के मामले में सबसे अव्वल आ जाएगा तो क्या बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप साबित होगी या फिर यह वरदान बन कर सामने आएगी। जनसंख्या बढ़ने से सीमित इलाके में लोग बढ़ते जा रहे हैं जिससे जमीन के भाव बढ़ते जा रहे हैं और आम लोगों के लिए जमीन खरीदना मुश्किल हो गया है। जहां पहले लोगों के पास कई कई खेत, प्लॉट और मकान हुआ करते थे अब लोगों के पास बेहद कम मात्रा में खेत और छोटे-मोटे घर ही बचे हैं। इसके अलावा देश की प्रति व्यक्ति आय पर भी असर पड़ रहा है। घरेलू चीजों की मांग बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था को संभालना आप नौजवानों के हाथ में है। दूसरी ओर जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, नदियां दूषित हो रही हैं, वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है तथा अन्य प्रकार के प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

केंद्र सरकार को ऐसी जनसंख्या नीति तैयार करने की आवश्यकता है जो न केवल व्यक्तियों की संख्या की अनियंत्रित वृद्धि पर अंकुश लगाए बल्कि जनसंख्या के अनियंत्रित आवागावन पर रोक लगाए। परिवार नियोजन को उस दलदल से बाहर निकालने की आवश्यकता है जिसमें यह फंस चुका है इसके लिए कार्यक्रम को अंदर से देखा जाना होगा तथा इसे स्वयं को अपने अधिकार के अंतर्गत विकास का निवेश मानना होगा, परिवार नियोजन को पुनः उसके पैरो पर खड़ा किए जाने के लिए उपायों को लागू करना होगा। जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा, मात्र समझाने-बुझाने से ही सफलता अर्जित की जा सकती है, पर अतिशय जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में आवश्यक है कि भारत जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए ठोस नीति को आकार दे। इस पर विचार करे कि भारत के लिए अनुकूलतम जनसंख्या क्या हो? अभी तक जितनी भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी है उसका सकारात्मक असर देखने को नहीं मिला।

जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है कि भारत में बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय, निर्धनता में वृद्धि, मकानों की समस्याएं, कीमतों में वृद्धि, कृषि विकास में बाधा, जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक व्यय, अपराधों में वृद्धि तथा शहरी समस्याओं में वृद्धि जैसी ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। पूंजीगत साधनों की कमी के कारण रोजगार मिलने में कठिनाई सामने आ रही है। ऐसे में अगर राज्यों में ज्यादा बच्चे की वकालत की जाएगी, तो हालत और भी बदतर हो जाएंगे।

अविनाश खेतान
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

ट्विटर

चुनाव में जितने ज्यादा दल होंगे, उतना ज्यादा खर्च होगा। विस के खर्च को देखते हुए यदि लोकसभा चुनाव में भी खर्च किया गया, तो डेढ़ लाख करोड़ रुपया व्यय होंगे।

डॉ. एन भास्कर, सीएमएस निदेशक

चुनाव में राजनीतिक दलों के खर्च को सीमित नहीं किया गया, तो यह लोकतंत्र को चौपट कर देगा। आज नेता किसी भी हाल में चुनाव जीतने की मंशा रखने लगे हैं।

योगेंद्र यादव, विश्लेषक

सत्यार्थ

छोटे काम खराब नहीं होते

एक बार एक युवक ने एक संत से कहा कि महाराज, मैं जीवन में सर्वोच्च शिखर पाना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मैं निम्न स्तर से शुरुआत नहीं करना चाहता। क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं, जो मुझे सीधे सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दे। संत बोले- अवश्य बताऊंगा। पहले तुम आश्रम के बगीचे से सबसे सुंदर गुलाब का फूल लाकर मुझे दो, लेकिन एक शर्त है। वह यह कि जिस गुलाब को तुम पीछे छोड़ जाओगे, उसे पलटकर नहीं तोड़ोगे। युवक यह आसान सी शर्त मानकर बगीचे में चला गया। वहां एक से एक सुंदर गुलाब खिले थे। जब भी वह एक गुलाब तोड़ने के लिए आगे बढ़ता, उसे कुछ दूरी पर उससे भी अधिक सुंदर गुलाब नजर आता और वह उसे छोड़ आगे बढ़ जाता। ऐसा करते-करते वह बगीचे के मुहाने पर जा पहुंचा, लेकिन यहां उसे जो फूल नजर आए, वे एकदम मुरझाए हुए थे। आखिरकार वह फूल लिए बिना ही वापस आ गया। उसे खाली हाथ देख संत ने पूछा- क्या हुआ बेटा, गुलाब नहीं लाए? युवक बोला- बाबा, मैं बगीचे के सुंदर और ताजा फूलों को छोड़कर आगे बढ़ता गया, मगर अंत में केवल मुरझाए फूल ही बचे थे। आपने मुझे पलटकर फूल तोड़ने से मना किया था। इसलिए मैं ताजा और सुंदर फूल नहीं तोड़ पाया। इस पर संत मुस्करा कर बोले- जीवन भी इसी तरह से है। इसमें शुरुआत से ही कर्म करते चलना चाहिए। सफलता शुरू के काम में छिपी रहती है। जो सर्वोच्च की लालसा में आगे बढ़ते रहते हैं, अंत में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि छोटे काम करने के बाद ही व्यक्ति को बड़े काम करने का मौका मिलता है। सीधा बड़ा काम किसी के हाथ नहीं आता।

रेनू सैनी

मैटिस को हटाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी सफाई, कहा- 'सोच-समझकर लिया फैसला'

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि रक्षा मंत्री जिम मैटिस को उन्होंने सोच समझ कर हटाया है. यह मैटिस के उस दावे के ठीक विपरीत है कि उन्होंने कई मामलों पर ट्रंप से असहमति की वजह से अपने पद से इस्तीफा दिया है. कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने पूर्व रक्षा मंत्री पर तीखा हमला बोला. ट्रंप के बयान के समय कार्यवाहक रक्षा मंत्री पैट्रिक शैनाहन भी उनके बगल में बैठे हुए थे.

अफगानिस्तान में जारी सुरक्षा संकट और युद्धग्रस्त देश में अमेरिकी खर्चों पर अफसोस जाहिर करते हुए ट्रंप ने कहा, 'मैटिस ने मेरे लिये क्या किया? उन्होंने अफगानिस्तान में कैसा काम किया?' ट्रंप ने कहा, 'मैं अफगानिस्तान में मैटिस के काम से खुश नहीं हूं और न ही खुश होने की कोई वजह है.' 'मैं उनके भले की कामना करता हूं. मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा काम करेंगे. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें पद से हटाया था, मैंने भी ऐसा ही किया. मैं परिणाम चाहता हूं.'

गौरतलब है कि मैटिस ने सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के ट्रंप के आदेश के बाद 20 दिसंबर को रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. अपने त्यागपत्र में मैटिस ने ट्रंप के साथ कई मामलों पर सहमति नहीं होने के संकेत दिये थे. अपने त्यागपत्र में मैटिस ने न सिर्फ देश बल्कि भावी रक्षा मंत्री के सामने आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया था. अमेरिकी सीनेट में विदेश संबंधों की समिति के सदस्य बॉब मेनेनडेज़ का कहना है कि मैटिस का इस तरह इस्तीफा बड़ा नुकसान है और और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाकाम और अराजकता में उलझी हुई विदेश नीति का वास्तविक संकेत है.

गौरतलब है कि मैटिस ने गुरुवार को इस्तीफा देने का एलान किया था . माना जा रहा है मैटिस ने यह फैसला ट्रंप के हाल ही में लिये गए उस फैसले से असहमति के चलते लिया है जिसमें ट्रंप ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे करीब 2 हजार अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही थी.

सार समाचार

अमेरिकी राजदूत ने जासूसी के आरोपी अमेरिकी नौसैनिक से रूस में मुलाकात की

मॉस्को। रूस में अमेरिकी राजदूत ने जासूसी के आरोपी पूर्व अमेरिकी नौसैनिक से बुधवार को मुलाकात की, जिसकी हिरासत ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजदूत जोन हंट्समैन ने मॉस्को के लेफोरतोवो कारागार में पॉल वेलन से मुलाकात की और बाद में उनके परिवार से टेलीफोन पर भी बात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, राजदूत हंट्समैन ने वैलन के प्रति सहयोग प्रकट करते हुए उन्हें दूतावास की ओर से सहायता की पेशकश की। राजनयिक ने यह मुलाकात 48 वर्षीय वैलन को पांच दिन पहले मॉस्को में हिरासत में लिया जाने के बाद की। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगर वैलन दोषी पाए गए तो उन्हें 20 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

पाकिस्तान का दावा, एलओसी के पास गिराया दूसरा भारतीय जासूसी ड्रोन

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की सीमा में उड़ रहे दूसरे 'भारतीय जासूसी ड्रोन' को गिराने का दावा किया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग 'इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस' के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, 'पाकिस्तानी सेना ने एक और भारतीय जासूसी क्वाडकॉप्टर गिराया।' उन्होंने कहा कि सतवाल सेक्टर में ड्रोन गिराया गया। मेजर जनरल गफूर ने मंगलवार को ड्रोन की तस्वीर के साथ ट्वीट करके दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के बाग सेक्टर में ''भारतीय जासूसी क्वाडकॉप्टर'' को गिराया है। भारतीय सेना ने इस दावे को खारिज किया था।

ब्राजील, इंडोनेशिया थाइलैंड से आ रहे एक के खास रसायन पर डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय की एक एजेंसी ने ब्राजील, इंडोनेशिया और थाइलैंड से आयात किए जाने वाले एक रसायनिक माल पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। यह रसायन रंग-रोगन और छपाई उद्योग में काम आता है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने मामले की जांच के बाद अपनी सिफारिश में कहा है कि इन देशों से ढलाई के लिए अनुपयुक्त नाइट्रोसेल्यूलोज रसायन को सामान्य दर से कम पर भारत को निर्यात किया जा रहा है। यह जांच नाइट्रेक्स केमिकल्स इंडिया की शिकायतपर की गयी थी। महानिदेशालय का निष्कर्ष है कि सामान्य से कम भाव पर आयात से घरेलू इकइयों को आघात लग रहा है। डीजीटीआर ने इस रसायन पर प्रति किलो 0.235- 0.906 डालर की दर से डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इस पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय करेगा।

सीरियाई विद्रोहियों और जिहादियों के बीच झड़प में 19 मरे

बेरूत। उत्तरी सीरिया में जिहादियों और विद्रोहियों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम 19 लोग मारे गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि पश्चिम अलप्पो प्रांत में आतंकवादी संगठन अलकायदा से संबंद्ध हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) और विद्रोहियों के एक संगठन के बीच झड़प हुई। एचटीएस ने सोमवार को आरोप लगाया कि विद्रोही संगठन नूरेद्दीनी अल जिंकी ने उसके पांच लड़ाकों की हत्या कर दी है। इसके बाद उसने पश्चिमोत्तर प्रांत इदलिब में विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। संगठन के प्रमुख रामी अब्देल रहमान ने कहा कि एचटीएस के 12 लड़ाके और दो नागरिकों सहित जिंकी समूह के पांच लोग मारे गए। इसके अलावा 35 लोग घायल हो गए।

रूस : विस्फोट के 72 घंटे बाद जिंदा निकला 10 महीने का बच्चा, 26 की मौत

मॉस्को। रूस की एक गगनचुंबी इमारत में नववर्ष की पूर्व संध्या पर हुए गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 26 हो गई है. उरल पहाड़ियों में स्थित मैगनितोगोर्स्क शहर में इमारत में विस्फोट के बाद से 15 लोग अब भी लापता हैं.

कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं बचावकर्ता

स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कड़ाके की ठंड (शून्य से करीब 27 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान) के बावजूद बचावकर्ता मलबे से शवों को निकाल रहे हैं. उन्होंने बताया कि भवन क्षतिग्रस्त होने के करीब 36 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाले गए 10 महीने के बच्चे को उसकी मां से मिलाया गया. हालांकि और लोगों के जिंदा बचे होने की संभावना कम हो गई है.

अधिकारियों ने निकाले 26 शव

आपात स्थिति से संबंधित मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि साढ़े चार बजे तक 26 शव निकाले गए जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं. इससे पहले दो बच्चों समेत छह लोगों को बचाया गया था.

विस्फोट की खबरों को रूस ने किया खारिज

ब्रिटिश मीडिया द गार्डियन में छपी एक ख़बर के मुताबिक रूस ने उन बातों से इनकार किया है जिनमें ये जानकारी सामने आई थी कि बिल्डिंग में विस्फोटक मिला है. नए साल के पहले हुए धमके में इस बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. लेकिन आवासीय बिल्डिंग में धमके के कारणों में विस्फोटक की बात को रूस ने सिरे से ख़ारिज कर दिया है. हालांकि, रूस का कहना है कि वो सभी संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं

तुर्की पुलिस ने हिरासत में लिए 12 संदिग्ध, आईएस से कनेक्शन होने का शक

अंकारा (एजेंसी)।

तुर्की ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह से संबंध रखने के आरोप में 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है. इनमें दो फ्रांसीसी महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी तलाश इंटरपोल को थी. सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलु ने बताया कि तुर्की के उत्तर पश्चिमी बुरसा प्रांत में आतंकवाद रोधी छापों के बाद फ्रांसीसी, सीरियाई और अल्जेरियाई नागरिकों समेत 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. इनमें से तीन महिलाएं हैं जिनमें से दो फ्रांसीसी महिलाओं की तलाश इंटरपोल को भी थी. इंटरपोल ने इनके खिलाफ रेड और ब्लू नोटिस जारी कर रखे थे.

पिछले साल भी हिरासत में लिए गए थे संदिग्ध

बता दें इससे पहले 31 और 28 दिसंबर को भी तुर्की की पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया था. तुर्की पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध विदेशी हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है. बता दें 31 दिसंबर को पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया था.

पुलिस को मिले कुछ जरूरी दस्तावेज

पुलिस ने सभी को तुर्की की राजधानी अंकारा में नए साल की पूर्व संध्या पर आतंकवादी गतिविधियों की आशंका के चलते इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं छापेमारी में पुलिस ने कुछ फर्जी दस्तावेज भी हासिल किए थे, जिनकी जानकारी गुप्त रखी गई थी. बता दें इसके पहले 28 दिसंबर को भी तुर्की पुलिस ने 52 संदिग्धों को हिरासत में लिया था.

अब जेल में झाड़ू पोछा खुद करेंगे नवाज शरीफ, इमरान सरकार ने नौकर देने से किया इनकार

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

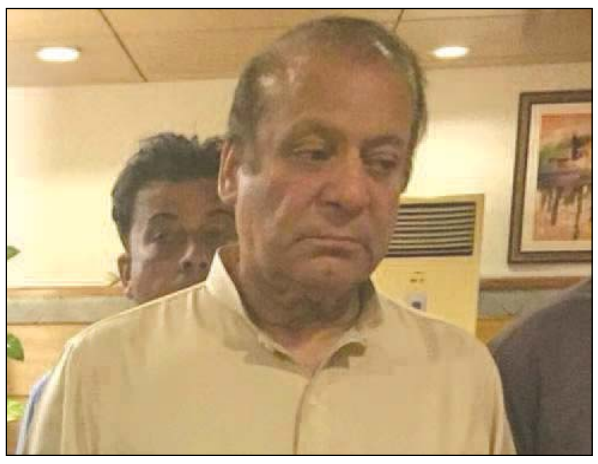

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जेल में अपनी कोठरी की साफ-सफाई खुद ही करनी होगी क्योंकि पंजाब की प्रांतीय सरकार ने उन्हें कैदी मुहैया कराने से बुधवार को इनकार कर दिया जो उनके सेवादार के तौर पर काम करता। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई। अल अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं और एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर वह सेवादार समेत अन्य बेहतर सुविधाओं के हकदार हैं।

डॉन समाचारपत्र के मुताबिक, पंजाब के जेल महानिरीक्षक शाहिद सलीम बेग ने बुधवार को कहा कि पंजाब सरकार ने शरीफ को बंदी मुहैया नहीं कराने का फैसला किया है जो उनके सेवादार के तौर पर काम करता। बेग ने कहा कि शरीफ को अपनी कोठरी खुद ही व्यवस्थित रखनी होगी।

जेल प्रमुख ने कहा कि अल अजीजिया स्टील मिल्स/हिल मेट इस्टैब्लिशमेंट मामले में मिली सात साल की 'सश्रम' कैद पूरी करने के लिए 'नवाज शरीफ को अपनी कोठरी स्वयं व्यवस्थित रखने को कहा गया है।' पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर की उपस्थिति में गवर्नर हाउस में, जेल महानिरीक्षक बेग ने कहा कि शरीफ का मामला अत्यंत संवेदनशील है और उन्हें जेल में उनकी बैरक से भी बाहर जाने नहीं दिया जा सकता।

कांग्रेस नेताओं से ट्रंप की बैठक रही बेनतीजा, अमेरिका में अब भी ठप्प है सरकारी कामकाज

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिकी सरकार के आंशिक रूप से ठप पड़े कामकाज पर गतिरोध को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच व्हाइट हाउस में बुधवार को हुई बैठक बेनतीजा रही. बैठक में अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण की ट्रंप की मांग को लेकर रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेट्स अपने-अपने रुख पर अड़े रहे.

ट्रंप इस दीवार के लिए 5.2 अरब डॉलर की निधि मांग रहे हैं और उनके मुताबिक अमेरिका में अवैध आव्रजकों के प्रवेश को रोकने के लिए इस दीवार का बनना बेहद जरूरी है. वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि इस तरह का कदम उठाना 'करदाताओं के धन की बर्बादी' है. सिचुएशन रूम में हुई इस बेनतीजा बैठक के बाद कांग्रेस नेता और ट्रंप शुक्रवार को एक बार फिर मिलने पर सहमत हुए हैं.

कांग्रेस के नवनिर्वाचित सदस्य बृहस्पतिवार यानि 116वीं कांग्रेस के पहले दिन को शपथ ले सकते हैं. डेमोक्रेटिक नेता नैंसी पेलोसी का अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स का अध्यक्ष बनना तय है. ट्रंप ने बैठक के बाद ट्वीट किया, ÷कांग्रेस के रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेट नेताओं के साथ सीमा सुरक्षा पर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई. दोनों पक्षों का फंडिंग विधेयक को पारित कराने के लिए साथ काम करना जरूरी है जो राष्ट्र एवं उसके लोगों की रक्षा करे- यह सरकार का प्रथम एवं सबसे जरूरी कर्तव्य है.'

वहीं पेलोसी ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि उनकी योजना सीमा दीवार के लिए वित्तपोषण के बिना खर्च विधेयक पर डेमोक्रेटिक कानून के साथ आगे बढ़ने की है. गुरुवार से हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स को बहुमत हासिल होगा.

यूनान ने बचाव अभियान में मदद के लिए तीन प्रवासियों को दी नागरिकता

एथेंस (एजेंसी)।

जंगल की आग की चपेट में आये दर्जनों लोगों को बचाने में मदद के लिए तीन प्रवासी मछुआरों को बुधवार को यूनान की नागरिकता दी गई। इस आग में 100 लोगों की मौत हो चुकी है। आग की लपटों से बचने के लिए लोगों को समुद्र में जाना पड़ गया था। यूनान के राष्ट्रपति प्रोकोपिस पावलोपोलोस ने अल्बानिया के 35 वर्षीय गनी ज्हेका और मिस्र के 50 वर्षीय इमाद अल खैमी और 46 वर्षीय महमूद इब्राहिम मूसा के सम्मान में तथा प्रवासी विरोधी भावना से निपटने के वास्ते 'यूरोप को एक संदेश' देने के लिए एक समारोह आयोजित किया था। इन तीनों लोगों ने पानी से उन लोगों को निकाला, जो एथेंस से पूर्व माटी में समुद्र तट वाले रिजॉर्ट पर लगी इस भयावह आग से बचकर पानी में चले गये थे, जिन्हें भारी धुएं की वजह से सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी। गौरतलब है कि इन तीनों ने 23 जुलाई को लगी आग के बाद भी तट के पास बचे हुए लोगों को गाइड किया था। उस आग में सैकड़ों घर जल गये थे।

ऑस्ट्रेलिया के खेत में दिखा ऐसा नजारा, वीडियो देख आंखों पर नहीं होगा यकीन

सिडनी (एजेंसी)।

तूफान जैसे हालात में अगर आप फंस जाएं, तो सुरक्षित घर पहुंचने के लिए क्या करेंगे। जाहिर सी बात है जो भी साधन उपलब्ध होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ही नजारा सामने आया है ऑस्ट्रेलिया में, जहां इस समय कुनुनूर्रा तूफान कहर बरपा रहा है।

भारी बारिश हुई तो मेढक भी सेफ जगह पर जाने के लिए कोशिश करने लगे। इसी दौरान करीब एक दर्जन मेढक 11 फीट लंबे अजगर पर ही सवार हो गए। इस फोटो को एन्ड्रू मॉक ने ट्विटर पर सबसे पहले पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि उनके भाई पॉल मॉक ने इस तस्वीर को खींचा था। सोशल साइट पर शेयर किए जाने के बाद ये फोटो वायरल हो गई है। इस घटना का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह नजारा एक किसान पॉल मॉक के खेत में देखने को मिला। पॉल ने ही इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वो कुनुनूर्रा तूफान के बाद अपने खेत को देखने आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सांप और मेंढकों को एक साथ देखा तो उनके होश उड़ गए। पॉल ने बताया कि रात के करीब 1÷30 बजे उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बाहर भारी बारिश के कारण चारों तरफ पानी भर गया है। इससे बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। इन हालात में उन्होंने अपने खेतों को देखने का फैसला किया। स्थानीय मीडिया में पॉल के हवाले से लिखा गया है कि खेतों में काफी पानी भर चुका था, जिससे मेंढक ऊपर की तरफ आ गए थे। मैंने बहुत सारे मेंढक एक ही जगह देखे, जिसके बाद मैं दूसरी तरफ गया तो मेंढक अजगर के ऊपर बैठे हुए थे। जब मैंने पास जाकर देखा तो सांप के ऊपर मेंढक बैठे थे और सवारी का मजा ले रहे थे। पॉल ने बताया कि उनके खेत में हजारों मेंढक थे। यह जीव अधिकतर रात को ही निकलते हैं क्योंकि इन्हें गर्मी पसंद नहीं होती, मगर वे बारिश को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि अजगर करीब 3.5 मीटर लंबा था और ऐसे मेंढक अधिकतर अमेरिका में पाए जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी संख्या बढ़ रही है। स्ढ्ढङ्गढ्ढह्स्नह नाम के यूट्यूब चैनल ने इस वीडियो को शेयर किया है।

माली में शिकारियों-पशुपालकों के संघर्ष में 37 लोगों की मौत : सरकार

बमाको (एजेंसी)।

मध्य माली में फुलानी पशुपालकों के एक गांव पर पारंपरिक डोगोन शिकारियों के हमले में मंगलवार को 37 लोग मारे गए। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, मोप्ती क्षेत्र में बंकास के निकट कुलोगोन गांव में पारंपरिक डोजो शिकारियों के कपड़े पहने हुए लोगों ने हमला किया। डोजो शिकारी जातीय समूह डोगोन से जुड़े हुए हैं। बयान के मुताबिक, 37 लोगों की मौत के अलावा कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं और कई मकान भी जलाए गए हैं। हमले के प्रत्यक्षदर्शी एक सुरक्षा सूत्र और एक व्यक्ति ने भी इसके लिए डोगोन को ही जिम्मेदार बताया था। उसने मृतकों की संख्या 33 बतायी थी। फुलानी समुदाय के अलाये यातारा ने बताया, ''हमले में हमारे ग्राम प्रधान मूसा दिआलो, एक बुजुर्ग महिला और बच्ची सहित उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है।'' फुलानी और डोगोन समुदायों के बीच चारागाह, जमीन और पानी को लेकर विवाद के कारण अकसर हिंसक संघर्ष होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2018 में इस क्षेत्र में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।

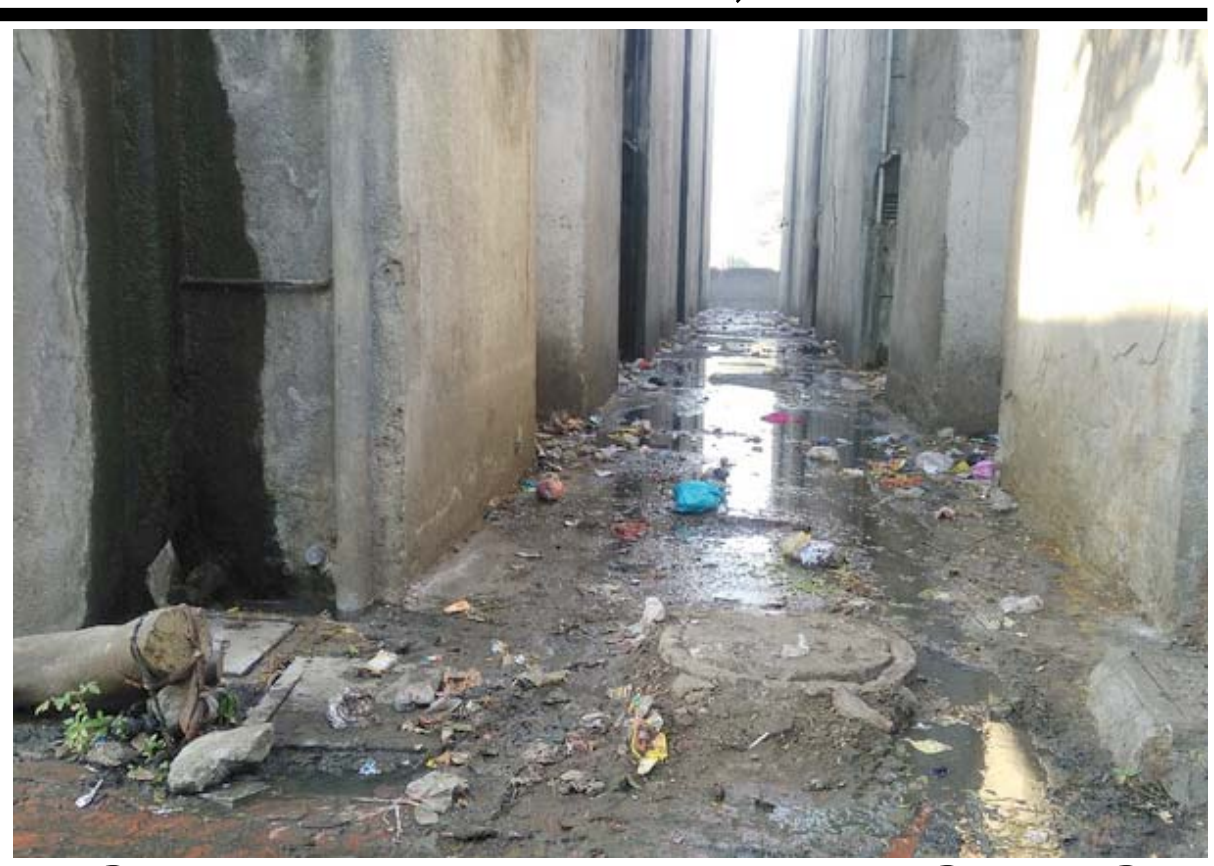

स्वच्छ भारत मिशन केवल कागजों में

सूरत । एक तरफ जहां जिला ग्राम विकास एजेंसी द्वारा स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिता का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है वहीं दूसरी तरफ शहर के पांडेसरा क्षेत्र में चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है । जो स्वच्छ भारत मिशन के इस अभियान को मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में तो यही लगता है कि केंद्र सरकार का स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है।

साउथ जोन में फिर चला अवैध निर्माण पर हथोड़ा

सूरत। साउथ जोन उधना के एडीशनल सिटी इंजीनियर तथा जोनल चीफ और कार्यपालक इंजीनियर के निर्देश तथा मार्गदर्शन में बुधवार को उधना जोन के पांडेसरा के मनपा शॉपिंग सेंटर की दुकान नंबर 1 तथा 2 के मालिक द्वारा मार्जिन की जगह में किए गए अवैध निर्माण को तोड़कर कब्जा खाली कराया गया इस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पालिका की तरफ से दुकान मालिक को पहले नोटिस दिया गया था जिसके बाद दुकान मालिक ने नोटिस के विरुद्ध कोर्ट में अर्जी की थी परंतु कोर्ट द्वारा और जी रद्द कर दिए जाने पर पालिका ने बुधवार को अवैध निर्माण ध्वस्त कर जगह खाली कराया।

सूरत। एक तरफ साउथ जोन अवैध निर्माण पर हथोड़ा चला रहा है लेकिन इन बिल्डिंगों पर उसके अधिकारियो की मेहरबानी से किसी का ध्यान नहीं पड़ रहा है।

सूरत में पहली बार 5100 कुंडीय महायज्ञ का भव्य आयोजन 6 जनवरी से

सूरत । महर्षि सफला देव विहंगम योग संस्थान तथा अखिल भारतीय विहंगम योग संत समाज गुजरात के तत्वावधान में सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज तथा संत प्रवर विज्ञान देव महाराज के पावन सानिध्य में 6 जनवरी 2019 से 5100 कुंडीय महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। महायज्ञ 6 जनवरी, रविवार की सुबह 9:00 बजे से सी.बी. पटेल स्पोर्टस कंपलेक्स के निकट मणिबा पाटी प्लाट के सामने वीआईपी रोड सूरत में आरंभ होगा। गुजरात में पहली बार सूरत में 5100 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। योग संस्थान विश्व शांति के लिए कर रही है कार्यक्रम के संयोजक रामवृक्ष रात महाराज ने बताया कि जिस प्रकार त्रेता युग में महाराजा दशरथ में महर्षि श्रृंगी द्वारा पुत्र यज्ञ का अनुष्ठान कराया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रयाग की पावन भूमि में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया उसी प्रकार वैदिक पद्धति से विश्व शांति हेतू महायज्ञ संपन्न कराया जाएगा समग्र विश्व में सुख शांति तथा समृद्धि की कामना के लिए आयोजित यज्ञ के बारे में जानकारी देते हुए रामवृक्ष दास महाराज ने बताया कि यज्ञ द्वारा न केवल मनुष्य मात्र का कल्याण होगा अपितु समस्त सृष्टि का कल्याण होगा यज्ञ आहुति से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण शुद्ध होगा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तथा वायुमंडल में ओजोन का निर्माण होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म वितरण शुरू

7 स्थानों पर 3951 आवासों का होगा आवंटन

सूरत। सूरत महानगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना फेस 2 अंतर्गत शहर के अलग-अलग सात जगहों पर 3951 आवासों के लिए फार्म का वितरण 3 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। यह फॉर्म आईसीआईसीआई बैंक के 16 शाखाओं पर उपलब्ध है। फार्म वितरण के पहले दिन ही लोगों की लंबी कतारें बैंक की शाखाओं पर देखने को मिली। सूरत महानगर पालिका के अफॉर्डेबल हाउसिंग विभाग द्वारा पहले भी मुख्यमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ईडब्ल्यूएस तथा एलाइजी आवासों का निर्माण किया गया है ।अच्छी क्वालिटी तथा बेहतरीन सुविधा के चलते लोगों का आकर्षण इन आवासों के प्रति बढा है जिसके कारण पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाखों की संख्या में लोगों ने फॉर्म भरा था। इसमें से बहुत सारे लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में आया है। महानगर पालिका ने वेटिंग लिस्ट वाले लाभार्थियों को अलग से सम्मति पत्र भरने को कहा है। जिससे उन्हें अन्य जगह पर उपलब्ध फ्लैटों में आवंटन किया जा सके।

लोक रक्षक दल के परीक्षार्थियों के लिए सूरत में होगी रहने और खाने की सुविधा

सूरत । भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर के अध्यक्ष नितिन भाई भुजियावाला ,महामंत्री मदन सिंह ऑटोदरिया ,डॉक्टर जगदीश पटेल तथा किशोर भाई बिंदल ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि 6 जनवरी को सूरत में आयोजित होने वाले लोक रक्षक दल की परीक्षा में परीक्षार्थियों के सूरत में रहने तथा भोजन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। लोक रक्षक दल की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए शहर भाजपा अध्यक्ष नितिन भजियावाला ने बताया कि आगामी 6 जनवरी 2019 को लोक रक्षक दल की परीक्षा सूरत में होनी है जिसमें संपूर्ण गुजरात से परीक्षार्थी सूरत आएंगे। परीक्षा देने वालों में से ज्यादातर परीक्षार्थी एक दिन पहले ही 5 जनवरी को सूरत पहुंच जाएंगे ।ऐसे में परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े शहर भाजपा द्वारा उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है।

सूरत में गरीब कल्याण मेला आज

सूरत । राज्य सरकार की विविध लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थल पर गरीबों को मिल सके इस उद्देश्य से सूरत में गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है 4 जनवरी 2019 की सुबह 9:30 बजे कामरेज के विद्या भारती केलावानी मंडल प्रांगण में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में जिले के 26, 233 जरूरतमंदों को 25.30 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी । राज्य के स्वास्थ्य मंत्री किशोर भाई कानाणी तथा गुजरात राज्य पर्यटन निगम के चेयरमैन कमलेश भाई पटेल के हाथों लाभार्थियों को हाथों हाथ साधन सामग्री प्रदान की जाएगी।

बजाज फाइनेंस के नाम पर एक और ठगी

सूरत । बजाज फाइनेंस के नाम पर एक और ऑनलाइन ठगी का मामला प्रकाश में आया है । प्राप्त जानकारी अनुसार शहर के ए के रोड धर्मनगर सोसाइटी में रहने वाले रत्न कलाकार योगेश धीरुभाई ने बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर के नाम पर फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। वराछा पुलिस में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार यह बताया गया है कि बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर के नाम पर अज्ञात व्यक्ति ने फरियादी से उसके बैंक की सभी डिटेल जानकर उसके अकाउंट से पैसे उड़ा कर ठगी की है ।फोन पर फरियादी की अकाउंट की सारी डिटेल जानने के बाद उसके अकाउंट से ?40330 निकाल लिए। योगेश भाई की शिकायत पर वराछा पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ।बजाज फाइनेंस के नाम पर सूरत शहर में ठगी का यह तीसरा माल मामला है पुलिस में इस तरह के अपराध का शिकार होने से बचने के लिए शहर के नागरिकों को किसी भी हिस्से में नानी की सलाह दी गई है।

भटार के व्यापारी तथा डिंडोली की महिला के गले से सोने के चेन की लूट

सूरत। शहर के खटोदरा भटार चार रास्ता ओवर ब्रिज के पास व्यापारी के गले से 60000 कीमत की सोने की चेन झपट कर दो झपट मार फरार हो गए जिसकी शिकायत खटोद्रा पुलिस में दर्ज कराई गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार वेसू के सुकून रेसीडेंसी में रहने वाले अश्वनी कुमार विवेक कुमार गुप्ता बुधवार की रात अपनी दुकान से घर जा रहे थे तभी भटार चार रास्ता ओवर ब्रिज के पास काले रंग की मोटरसाइकिल पर मंकी कैप पहने आए दो अज्ञात बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन झपट कर भाग गए । कपोदरा पुलिस ने चेन झपटमारी का मामला दर्ज कर घटना वाले जगह की निरीक्षण के बाद अज्ञात चोरों के विरुद्ध जा की कार्रवाई शुरू कर दी है वही डिडोली के मधुरम सर्कल के निकट दीप दर्शन स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र तथा चैन लूटकर बदमाश फरार हो गए जिसकी शिकायत महिला द्वारा डिंडोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है दिल्ली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार तापी जिला की मूल वर्तनी तथा वर्तमान में डिंडोली के रॉयल स्टार टाउनशिप में रहने वाली दीपाली पंकज भाई मिस्त्री बुधवार की शाम डिंडोली मधुरम सर्कल के निकट एक्टिवा से जा रही थी तभी पीछे से स्पोर्ट ?स बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनके गले से मंगलसूत्र तथा सोने की चेन छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने महिला की शिकायत पर लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)